SarkariExam.com

10 सितम्बर 2021

1. 8 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस

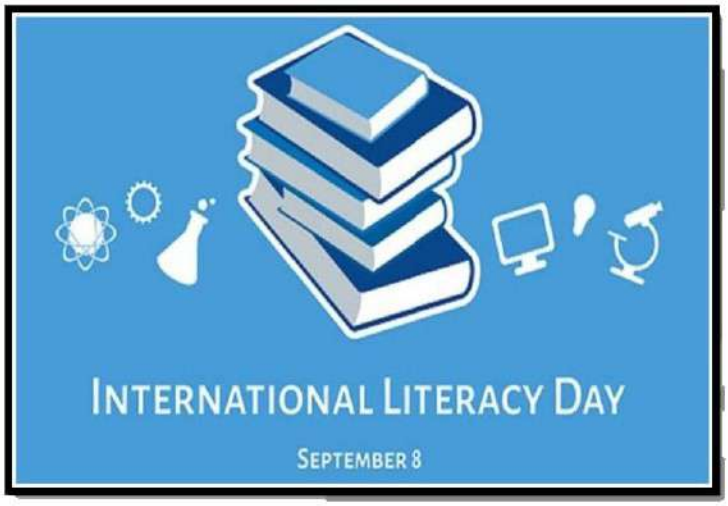

- व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व को याद दिलाने के लिए हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस (International Literacy Day) मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम "Literacy for a human-centred recovery: Narrowing the digital divide" है।
- यूनेस्को द्वारा 26 अक्टूबर, 1966 को यूनेस्को के सम्मेलन के 14वें सत्र में इस दिवस की घोषणा की गई थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 1967 में मनाया गया था। यह परंपरा अब 50 से अधिक वर्षों से प्रतिवर्ष आयोजित की जा रही है। व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व और अधिक साक्षर समाज बनाने के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को याद दिलाने के उद्देश्य से इस दिन की घोषणा की गई थी।

साक्षरता और सतत विकास लक्ष्य

- साक्षरता लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ-साथ सतत विकास के लिए इसके 2030 एजेंडा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। SDG का लक्ष्य 4 यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि सभी युवा, पुरुषों और महिलाओं सहित वयस्कों का पर्याप्त अनुपात 2030 तक साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करें।

भारत में साक्षरता

- 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में कुल 74.04% जनसँख्या साक्षर हैं। पिछले दशक (2001-11) की तुलना में इसमें 9.2% की वृद्धि हुई। यूनेस्को इस बात पर प्रकाश डालता है कि, भारत को 2060 तक सार्वभौमिक साक्षरता हासिल करने में और 50 साल लगेंगे।

SarkariExam.com

2. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 'प्राण' पोर्टल किया लॉन्च

- 07 सितंबर, 2021 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 'प्राण' नामक एक पोर्टल लॉन्च किया। 'प्राण' पोर्टल का उपयोग राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme – NCAP) की प्रगति को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा ताकि सभी को स्वच्छ हवा और नीला आसमान सुनिश्चित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का पालन किया जा सके।
- इस पोर्टल को गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment Cities – NC) में 'International Day of Clean Air for Blue Skies' के अवसर पर लॉन्च किया गया था।
- गैर-प्राप्ति वाले शहर वे शहर हैं जो 5 साल की अवधि में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहे। पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) 2024 तक भारत में पार्टिकुलेट मैटर (PM10 के साथ-साथ PM2.5) सांद्रता में 20-30% की कमी हासिल करना चाहता है।
- 'प्राण' पोर्ट्ल शहर की हवा कार्य योजना के कार्यान्वयन की भौतिक और वित्तीय स्थिति पर नज़र रखने में मदद करेगा। यह जनता को वायु गुणवत्ता के बारे में जानकारी भी प्रसारित करेगा।
- इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारत ने 132 NC/मिलियन प्लस शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए शहर-विशिष्ट कार्य योजनाओं को तैयार किया है और इसे लागू किया जा रहा है। यह मिट्टी और सड़क की धूल, वाहन, घरेलू ईंधन, निर्माण सामग्री और उद्योगों जैसे शहर-विशिष्ट वायु प्रदूषण स्रोतों को लक्षित करता है।

3. इंडियन एयर फोर्स को मिलेंगे स्पेन के अत्याधुनिक 56 C-295 MW विमान

- 08 सितंबर, 2021 को सुरक्षा मामलों संबंधी समिति (CCS) ने एयरोस्पेस क्षेत्र में मेक-इन-इंडिया पहल के तहत भारतीय वायु सेना के लिये 56 सी-295 मेगावाट (56 C-295 MW) क्षमता वाले मध्यम परिवहन विमान की खरीद को मंज़ूरी दे दी है। 56 सी-295 एमडब्ल्यू (C-295 MW) विमान को एयरबस डिफेंस एंड स्पेस एस.ए, स्पेन से खरीदा जाएगा।

- **56 सी-295 एमडब्ल्यू**
- यह 56 सी-295 एमडब्ल्यू समकालीन तकनीक के साथ 5-10 टन क्षमता का परिवहन विमान है। इसमें तेज़ी से प्रतिक्रिया और सैनिकों एवं कार्गो की पैरा ड्रॉपिंग के लिये एक रीयर रैंप (Rear Ramp Door) है।
- इसे स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट (Electronic Warfare Suite) के साथ स्थापित किया जाएगा। यह भारतीय वायु सेना के एवरो-748 (Avro-748) विमानों के पुराने बेड़े की जगह लेगा।
- एवरो-748 विमान एक ब्रिटिश मूल के ट्विन-इंजन टर्बोप्रॉप (British-origin twin-engine turboprop), सैन्य परिवहन और 6 टन माल ढुलाई क्षमता वाले मालवाहक विमान हैं।
- **परियोजना क्रियान्वयन**
- एयरबस डिफेंस एंड स्पेस (Airbus Defence and Space) और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (Tata Advanced Systems Limited-TASL) एयरोस्पेस क्षेत्र में मेक-इन-इंडिया पहल के तहत वायु सेना को नए परिवहन विमान से लैस करने की परियोजना को संयुक्त रूप से क्रियान्वित करेंगे।
- एयरबस पहले 16 विमानों को उड़ान भरने की स्थिति में आपूर्ति करेगी, जबकि शेष 40 को TASL द्वारा भारत में असेंबल किया जाएगा।

4. बाड़मेर में इंडियन एयर फोर्स के लिए इमरजेंसी नेशनल हाईवे पट्टी का हुआ लोकार्पण

- 09 सितंबर 2021 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के बाड़मेर के गंधव-बाखासर खंड में नेशनल हाईवे-925 पर बने 'इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड (ELF)' का उद्घाटन किया।
- इसके बाद भारत ने पाकिस्तान से सटी सीमा पर अपना शक्ति प्रदर्शन किया और हाईवे पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग की। पाकिस्तान सीमा से केवल 40 किलोमीटर दूरी पर भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) के सुखोई और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने अपना दम दिखाया।
- केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय वायुसेना के स्पेशल विमान से यहां पहुंचे थे, जिसकी लैंडिंग इसी एयर स्ट्रिप पर की गई थी।
- **भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग**
- एनएच-925 भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसका इस्तेमाल वायुसेना के विमानों को आपात स्थिति में उतारने के लिए किया जाएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बाड़मेर-

जालोर की सीमा पर देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप तैयार की गई है।

- **आपातकालीन पट्टी का निर्माण**
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने भारतीय वायु सेना के लिए आपातकालीन स्थिति में विमान उतारने के लिए एनएच-925ए के सट्टा-गंधव खंड के तीन किलोमीटर के हिस्से पर इस आपातकालीन पट्टी का निर्माण किया है।
- ईएलएफ (ELF) को निर्माण 19 महीने के अंदर पूरा किया गया है। इसका निर्माण कार्य जुलाई 2019 में शुरू किया गया था और जनवरी 2021 में यह तैयार हो गया था। भारतीय वायुसेना (आईएएफ) और एनएचएआई की देखरेख में 'जीएचवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' ने इसका निर्माण किया है।
- **तीन हेलीपैड का निर्माण**
- इस परियोजना में आपातकालीन लैंडिंग पट्टी के अलावा कुंदनपुरा, सिंघानिया और बाखासर गांवों में भारतीय वायु सेना/भारतीय सेना की आवश्यकताओं के अनुसार तीन हेलीपैड का निर्माण किया गया है, जो पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भारतीय सेना और सुरक्षा नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण का आधार होगा।
- **इन जगहों पर भी सुखोई लैंड कर चुका है**
- इससे पहले उत्तर प्रदेश के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भी सुखोई लैंड कर चुका है। बाड़मेर में 09 सितंबर को हुई इस शुभ शुरुआत से पहले 08 सितंबर को 3 घंटे लैंडिंग की प्रैक्टिस की गई थी।
- **सुखोई लड़ाकू विमान ने फ्लाइपास किया**
- रनवे पर सुखोई लड़ाकू विमान ने फ्लाइपास किया, साथ ही जगुआर और एयरफोर्स के अन्य विमान भी इस दौरान यहां पर दिखाई दिए। ये एयरस्ट्रिप भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास ही है, ऐसे में किसी विपरीत परिस्थिति में इसकी अहमियत सबसे अधिक होगी। हाइवे पर इस तरह की एयरस्ट्रिप युद्धक परिस्थितियों में अपना अहम योगदान देती है।
- **भारतमाला परियोजना (Bharatmala Pariyojana)**
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017-18 से भारतमाला कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की महत्त्वाकांक्षी 'भारतमाला परियोजना' के प्रथम चरण के तहत 5,35,000 करोड़ रुपए की लागत से 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का49-* निर्माण किया जाएगा। इसके अंतर्गत आर्थिक कॉरिडोर, फीडर कॉरिडोर और इंटर कॉरिडोर, राष्ट्रीय कॉरिडोर, तटवर्ती सड़कें, बंदरगाह संपर्क सड़कें आदि का निर्माण किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अवधि वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक है। चरण-1 में कुल 34,800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाना है, जिसमें शामिल हैं:

1. 5,000 किलोमीटर राष्ट्रीय कॉरिडोर।
2. 9,000 किलोमीटर आर्थिक कॉरिडोर।
3. 6,000 किलोमीटर फीडर कॉरिडोर और इंटर कॉरिडोर।
4. 2,000 किलोमीटर सीमावर्ती सड़कें।
5. 2,000 किलोमीटर तटवर्ती सड़कें एवं बंदरगाह संपर्क सड़कें।
6. 800 किलोमीटर हरित क्षेत्र एक्सप्रेस वे।
7. 10,000 किलोमीटर अधूरे सड़क निर्माण कार्य।

- इस परियोजना के तहत निर्माण कार्य करने वाली मुख्य एजेंसियाँ इस प्रकार हैं:- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग और

औद्योगिक विकास निगम तथा लोक निर्माण विभाग।

5. हेमंत धनजी बने ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज, ऐसा करने वाले पहले भारतीय मूल के शख्स

- सिडनी बैरिस्टर हेमंत धनजी एससी 07 सितंबर को न्यू साउथ वेल्स (NSW) के सुप्रीम कोर्ट में जज की भूमिका के लिए नियुक्त होने वाले पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई बन गए। धनजी को साल 1990 में एक लीगल प्रैक्टिशनर (Legal practitioner) के रूप में भर्ती कराया गया था और उनके पास तीन दशकों से ज्यादा का कानूनी अनुभव है।
- इस बात की जानकारी देते हुए भारत में ऑस्ट्रेलियाई हाईकमीशन ने एक ट्वीट में कहा कि "सिडनी बैरिस्टर हेमंत धनजी SC न्यू साउथ वेल्स सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई बन गए हैं। वो 1990 में एक लॉ प्रैक्टिशनर के रूप में भर्ती हुए, धनजी के पास तीन दशकों से अधिक का कानूनी अनुभव है।
- वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देश बहुत लंबे समय से एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध साझा कर रहे हैं और दिनों-दिन इन संबंधों में प्रगति देखी जा रही है।
- द्विपक्षीय व्यापार, रणनीतिक प्रयास, छात्र विनिमय कार्यक्रम, सतत् विकास के लिये समान प्रतिबद्धताओं ने भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को और अधिक गतिशील बना दिया है। इस बीच 11 सितंबर को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच टू-प्लस-टू मंत्रिस्तरीय स्वांद भी होने वाला है।

11 सितंबर को होने वाले टू-प्लस-टू मंत्रिस्तरीय संवाद

- दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 11 सितंबर को होने वाले टू-प्लस-टू मंत्रिस्तरीय संवाद में समग्र रक्षा और सुरक्षा संबंधों को और बढ़ाने तथा हिंद-प्रशांत में रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है।
- सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिस पायने और रक्षा मंत्री पीटर डटन के साथ बातचीत करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर कब्जा करने की पृष्ठभूमि में ऑस्ट्रेलिया के दोनों वरिष्ठ मंत्री दौरे पर आ रहे हैं। जयशंकर और सिंह की अपने समकक्षों के साथ अलग-अलग बैठकों में इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है।

6. श्रीनगर में आयोजित किया जा रहा है नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

- केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT), श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में 07 सितंबर को बेहतर जीवन के लिए नैनो प्रौद्योगिकी पर पाँच दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था।
- यह सम्मेलन 07 सितंबर से 11 सितंबर, 2021 तक चलेगा। यह सम्मेलन का 7वां संस्करण है। नैनोस्केल रिसर्च फैसिलिटी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली और अन्य सहयोगी संस्था के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। हाइब्रिड मोड में आयोजित इस सम्मेलन में देश भर से लगभग 300 प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे।
- नैनोटेक्नोलॉजी या नैनोटेक वह तकनीक है जिसमें किसी भी पदार्थ में परमाणु, आणविक और सुपरमॉलीक्यूलर स्तर पर परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें 1 से 100 नैनोमीटर तक के कण शामिल होते हैं।

7. आइसलैंड में कार्बन का अवशोषण करने वाले दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र को किया गया शुरू

- हाल ही में कार्बन का अवशोषण करने वाले दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र को आइसलैंड में चालू किया गया है जिसका नाम ओर्का प्लांट है। इस संयंत्र को हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और उसे पुनः भूमि में खनिज के रूप में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है।
- ऑपरेटरों के मुताबिक ओर्का प्लांट हर साल 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से बाहर निकाल सकता है। अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार यह लगभग 870 कारों से होने वाले उत्सर्जन के बराबर है। आइसलैंडिक शब्द ओर्का का अर्थ ऊर्जा है।
- कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्रित करने के लिए संयंत्र एक संग्राहक चेंबर में हवा खींचता है जिसके अंदर एक फिल्टर सामग्री होती है।
- एक बार जब फिल्टर सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड से भर जाती है तो संग्राहक बंद कर दिया जाता है और सामग्री से कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करने के लिए तापमान बढ़ा दिया जाता है जिसके बाद अत्यधिक

केंद्रित गैस एकत्रित की जा सकती है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ मिलाकर 1000 मीटर की गहराई पर डाल दिया जाता है ताकि यह खनिज में परिवर्तित हो सके।

8. निजी नौकरी में आरक्षण देने वाला देश का तीसरा राज्य बना झारखंड

- निजी नौकरियों में आरक्षण देने वाला झारखंड देश का तीसरा राज्य बन गया। इससे पहले आंध्र प्रदेश और हरियाणा की सरकारें अपने राज्य में ये नियम लागू कर चुकी हैं। झारखंड के लोगों को निजी नौकरियों में इसका फायदा मिलेगा। निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने वाला बिल झारखंड विधानसभा से बिना बहस के पारित हो गया। इससे प्राइवेट सेक्टर में प्रति माह 40 हजार रुपए तक की सभी मौजूदा नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण मिलेगा।
- वैसे झारखंड राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार विधेयक, 2021 मूल रूप से मार्च में विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया गया था। इसके बाद जांच के लिए इसे पैनल में भेजा गया था।

❑ **झारखंड की निजी नौकरियों में आरक्षण फिक्स**

- छह सदस्यीय चयन समिति की अध्यक्षता राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने की थी। मूल विधेयक में किए गए परिवर्तनों में संशोधित विधेयक में निजी क्षेत्र शब्द जोड़ना, इसका नाम बदलकर निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का झारखंड राज्य रोजगार विधेयक, 2021 करना शामिल था।
- नए संशोधनों ने वेतन ब्रैकेट को 30,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दिया गयाऔर इसमें एक नया क्लॉज भी जोड़ा गया, जिसने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस कानून के दायरे में ला दिया है।

9. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की

- भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 09 सितंबर, 2021 को ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की।

- इस शिखर सम्मेलन की थीम है- BRICS@15: Intra-BRICS cooperation for continuity, consolidation and consensus। भारत ने अपनी अध्यक्षता के लिए चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की है।
- इसमें बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, आतंकवाद का मुकाबला, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल और तकनीकी उपकरणों का उपयोग करना और लोगों से लोगों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ाना शामिल है।
- अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 'आज हम दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रभावशाली आवाज हैं।' उन्होंने सदस्यों को भारत की अध्यक्षता में पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए भी धन्यवाद दिया।
- पीएम ने कहा, 'इस साल कोविड-19 स्थिति के बावजूद 150 से अधिक ब्रिक्स मीटिंग और इवेंट आयोजित किए गए। इनमें से 20 से अधिक मिनिस्टेरियल लेवल के थे। हमने ब्रिक्स एजेंडा का विस्तार करने की कोशिश की। ब्रिक्स ने इस साल कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
- हमारे जल संसाधन मंत्री नवंबर में पहली बार ब्रिक्स प्रारूप में मिलेंगे।' इस बीच, पुतिन ने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी बलों और उसके सहयोगियों की वापसी से एक नया संकट पैदा हो गया है।
- यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि यह वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा को कैसे प्रभावित करेगा। पुतिन ने कहा, अफगानिस्तान को अपने पड़ोसी देशों लिए खतरा नहीं बनना चाहिए। आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी का सोर्स नहीं बनना चाहिए।

❑ ब्रिक्स

- ब्रिक्स दुनिया की पाँच अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं- ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिये एक संक्षिप्त शब्द (Abbreviation) है। ब्रिक्स कोई अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन नहीं है, न ही यह किसी संधि के तहत स्थापित हुआ है। इसे पाँच देशों का एकीकृत प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है।
- ब्रिक्स देशों के सर्वोच्च नेताओं का तथा अन्य मंत्रिस्तरीय सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किये जाते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मलेन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष B-R-I-C-S क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है।
- ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% है और इसका वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा लगभग 30% है। इसे महत्त्वपूर्ण आर्थिक इंजन के रूप में देखा जाता है और यह एक उभरता हुआ निवेश बाज़ार तथा वैश्विक शक्ति है।
- BRICS की चर्चा वर्ष 2001 में Goldman Sachs के अर्थशास्त्री जिम ओ' नील द्वारा ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के लिये विकास की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट में की गई थी। वर्ष 2006 में चार देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य बहस के अंत में विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठकों के साथ एक नियमित अनौपचारिक राजनयिक समन्वय शुरू किया।
- इस सफल बातचीत से यह निर्णय हुआ कि इसे वार्षिक शिखर सम्मेलन के रूप में देश और

सरकार के प्रमुखों के स्तर पर आयोजित किया जाना चाहिये। पहला BRIC शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस के येकतेरिनबर्ग में हुआ और इसमें वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

- दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को BRIC में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया गया और इसे BRICS कहा जाने लगा। मार्च 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार चीन के सान्या में तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
- ब्रिक्स का उद्देश्य अधिक स्थायी, न्यायसंगत और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिये समूह के साथ-साथ, अलग-अलग देशों के बीच सहयोग को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना है।
- ब्रिक्स द्वारा प्रत्येक सदस्य की आर्थिक स्थिति और विकास को ध्यान में रखा जाता है ताकि संबंधित देश की आर्थिक ताकत के आधार पर संबंध बनाए जाएँ और जहाँ तक संभव हो सके प्रतियोगिता से बचा जाए।

10. केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इंडिया रैंकिंग 2021 की जारी

- 09 सितंबर, 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा तैयार की गई इंडिया रैंकिंग 2021 (नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क) जारी की है।
- यह देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की छठी NIRF वार्षिक रैंकिंग सूची है। 2016 में अपने पहले वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय श्रेणी के साथ-साथ तीन विषय-विशिष्ट रैंकिंग रैंकिंग की घोषणा की गई थी। 2021 में कुल मिलाकर 4 श्रेणियां, अर्थात् विश्वविद्यालय, कॉलेज और अनुसंधान संस्थान और 7 विषय, अर्थात् इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, वास्तुकला, चिकित्सा, कानून और दंत चिकित्सा शामिल किए गए हैं। भारत रैंकिंग 2021 में पहली बार अनुसंधान संस्थानों को स्थान दिया गया है।

❑ **इंडिया रैंकिंग 2021 की मुख्य विशेषताएं:**

1. इस वर्ष 'विश्वविद्यालय श्रेणी' के तहत IISc बेंगलुरु पहले, JNU दूसरे, BHU तीसरे स्थान पर रहा है।

SarkariExam.com

2. नया शोध संस्थानों की श्रेणी में IISc बेंगलुरु पहले, आईआईटी मद्रास दूसरे और आईआईटी मुंबई तीसरे स्थान पर रहा है।
3. ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहा, वहीं IISc बेंगलोर दूसरे और IIT मुंबई तीसरे स्थान पर रहा है।
4. प्रबंधन विषय में भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद शीर्ष पर है।
5. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली लगातार चौथे वर्ष चिकित्सा क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर है।
6. जामिया हमदर्द फार्मेसी विषय में लगातार तीसरे साल सूची में सबसे ऊपर है।
7. मिरांडा कॉलेज ने लगातार पांचवें साल कॉलेजों में पहला स्थान बरकरार रखा है।
8. वास्तुकला विषय में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-आईआईटी खड़गपुर को पीछे छोड़ते हुए आईआईटी रुड़की पहली बार शीर्ष स्थान पर है।
9. नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलोर ने लगातार चौथे वर्ष विधि के लिए अपना पहला स्थान बरकरार रखा है।
10. मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज, मणिपाल ने "दंत चिकित्सा" श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया।

SarkariExam.com